

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(46) ग्राविवि/ग्रुप-5/PMAY-G/M-I/GoI/2017-18

जयपुर, दिनांक 09 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थाई वरीयता सूची में अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान कर शामिल किये जाने के क्रम में।

प्रसंग :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-11060/16/2017-RH-(M&T)dated 24.01.18

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में ऐसे लाभार्थियों जो योजना की पात्रता हेतु मापदण्ड पूरा करते हो को, स्थाई वरीयता सूची में जोड़े जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रासंगिक पत्र संलग्न के द्वारा उक्त कार्य सम्पादन में समान मापदण्ड की पालना बाबत निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की है :-

1. राज्य द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र परिवारों (Households) की पहचान किये जाने में निम्न प्रक्रिया की सुनिश्चिता की जावे।

अ) SECC-2011 के आंकड़ों के अनुसार परिवार आवासहीन, 0, 1 या 2 रूम कच्ची दीवार एवं कच्ची छत के आवास का धारी होना चाहिए।

ब) परिवार की पात्रता निर्धारण हेतु क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुबन्ध-1 में वर्णित स्वतः बहिर्वेशन हेतु निर्धारित 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार शामिल नहीं किया जावे अर्थात् ऐसे परिवारों को वरीयता सूची में शामिल होने हेतु पात्रता नहीं रखते है। निर्धारित 13 पैरामीटर निम्नानुसार है :-

1. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रु. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रु. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
11. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
12. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

उक्त के साथ ही स्वतः अन्तर्वेशन के लिए निर्धारित 5 मापदण्डधारी परिवार को अनिवार्य रूप से जोड़ा जावे :-

1. आश्रयविहीन परिवार।
2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

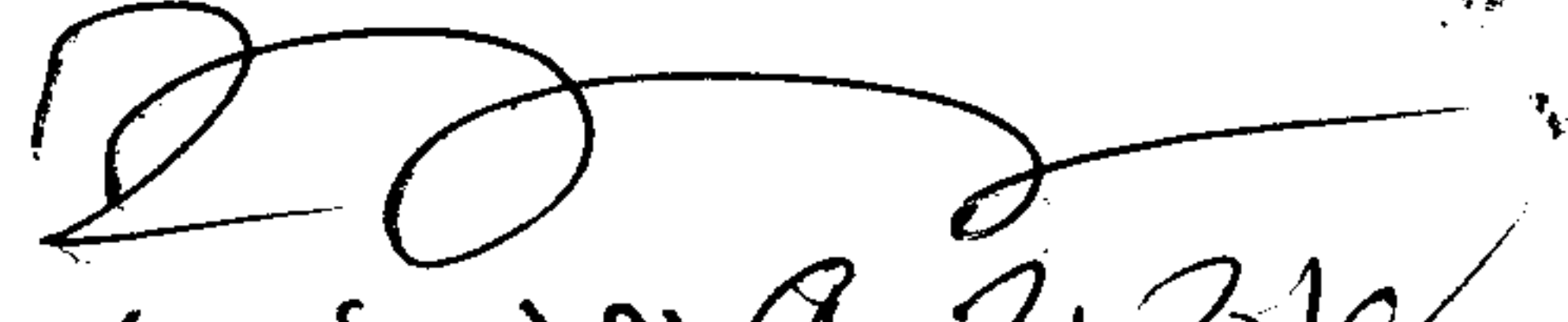
- स) घास/बांस/प्लास्टिक व हाथ से निर्मित केल्टू की छत को कच्ची छत एवं इन्हीं सामग्रियों व मड/बिना पकी ईंट, लकड़ी व पत्थर जिसमें मोर्टार काम में नहीं लिया गया हो, को कच्चा आवास माना जावे।
- द) ग्राम सभा द्वारा अपने प्रस्ताव/निर्णय में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि ग्राम सभा द्वारा उक्त सभी बिन्दुओं की जांच के आधार पर जांच कर इन व्यक्तियों को पात्र माना जाता है एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण में परिवार के मुखिया का नाम जिसको आवास आवंटन किया जाना है, का अंकन किया जावे।
- य) नाम जोड़ने हेतु दावा प्रस्तुत करने वाले परिवार का नाम सिस्टम जनरेटेड सूची में है एवं ग्राम सभा द्वारा हटा दिया गया है अथवा परिवार का नाम सिस्टम जनरेटेड सूची में नहीं है। उक्त दोनों परिस्थितियों में परिवार का नाम शामिल करने हेतु यथोचित कारण के साथ ग्रामसभा कार्यवाही विवरण में अंकित किया जावे।
- र) ग्राम सभा द्वारा चयनित परिवारों की सूची सक्षम प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो, को प्रस्ताव भिजवाये जावे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रामसभा से प्राप्त सूची और सीधे ही प्राप्त आवेदनों की जांच कर अपीलैट कमेटी को प्रस्तुत की जावेगी।
- ल) अपीलैट कमेटी द्वारा उक्त सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम अतिरिक्त सूची में शामिल किये जाने हेतु अनुशंसा की जावेगी।
2. राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया से जोड़े जाने वाले लाभार्थियों के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, का प्रमाण पत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को किया जाना है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत वर्तमान निवास एवं लाभार्थी द्वारा पक्के मकान के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल हेतु वर्तमान निवास/अन्य स्वामित्व भूमि की जीओ टैग फोटो अपलोड किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मोबाईल एप्लीकेशन एन.आई.सी. के सहयोग से तैयार की जा रही है। इस हेतु मंत्रालय द्वारा आवाससॉफ्ट पर जीओ टैगिंग, ग्रामसभा कार्यवाही विवरण अपलोड करने हेतु अलग से मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, उनमें निम्न सुविधाएँ उपलब्ध होगी :-
- अ. जीओ टैग फोटो लेते समय एप्लीकेशन में लाभार्थी के वर्तमान आवास की छत व दीवारमें उपयोग की गई सामग्री का विवरण दर्ज करने का प्रावधान होगा। उपलब्ध प्रावधान मार्गदर्शिका में वर्णित छत व दीवार की सामग्री जो कि कच्चे आवास हेतु मान्य किये गये हैं, उपलब्ध होंगे।
- ब. जीओ टैग फोटो केचरिंग के साथ ही योजना के लाभ हेतु 13 मापदण्डों, 5 स्वतः शामिल/अनिवार्य शामिल मापदण्ड एवं 5 डिपरिप्लेशन मापदण्डों को दर्ज करने की सुविधा होगी।
- स. मोबाईल एप्लीकेशन के उपयोग से लिये गये जीओ टैग फोटो को आवाससॉफ्ट के मॉड्यूल में ग्राम पंचायतवार स्टोर करने की सुविधा होगी।
- द. आवाससॉफ्ट मॉड्यूल में ग्रामसभा कार्यवाही विवरण जिसमें छूटे हुए पात्र व्यक्ति को पहचान कर जोड़े जाने के कारणों व परिवार मुखिया का नाम बाबत उक्त विवरण अपलोड किये जाने का प्रावधान भी होगा।
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्यों द्वारा उक्त कार्यवाही उपरान्त अपलोडेड फोटो का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन, स्पेस तकनीक द्वारा करवाया जावेगा। उक्त के साथ ही मंत्रालय द्वारा भौतिक सत्यापन भी करवाया जावेगा, जिसमें कच्चे मकान होने का सत्यापन सेक-2011 में वर्णित कच्चे मकान की परिभाषा की सामग्री छत व दीवार में उपयोग की गई है, के आधार, ग्रामसभा का निर्णय, सक्षम अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व इच्छुक लाभार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र या अन्य कोई अपीलैट प्राधिकारी की अनुशंसा को आधार बनाया जावेगा।



5. उक्त वर्णित समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक राज्य हेतु नये जोड़े जाने वाले नामों की संख्या का निर्णय लिया जावेगा, जिसके उपरान्त मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी से नये जोड़े गये नामों को सहायता प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।


उपरोक्त के परिपेक्ष्य में निर्देश है कि सभी जिले प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करने वाले परिवारों की पहचान व जोड़े जाने की उक्त वर्णित प्रक्रिया की शत-प्रतिशत पालना करवाते हुए दिनांक 28.02.2018 तक पूर्ण कर राज्य को सूची प्रेषित करे, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य स्तर से सक्षम परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त 31.03.2018 तक सूची प्रेषित की जा सके। उल्लेखनीय है कि सुलभ संदर्भ हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त अंग्रेजी भाषा का पत्र संलग्न है।

संलग्न - 342103/HR पर 24/1/2018


(सुदर्शन सेठी) 9/2/2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/ महात्मा गांधी नरेगा।
12. निजी सचिव, आयुक्त, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान।
13. निदेशक (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, राजस्थान।


अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि 9/2/18

J-11060/16/2017-RH(M&T)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 24th January 2018

To

The Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries
Department of Rural Development,
All State Governments / UT Administrations

Subject: Identification of additional beneficiaries for inclusion in the Permanent Wait List of PMAY-G – Procedure to be adopted – Reg.

Sir / Madam,

You are aware that the Framework for Implementation of PMAY-G provides for identification of households who though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. Further, Ministry of Rural Development has also issued an advisory to all the States / UTs vide letter No. J-11012/02/2016-RH, dated 6th July, 2017 to identify such left out households and upload the identified households on AwaasSoft. Accordingly, various State Governments have initiated the process of identification of households who though eligible have not been included in the PWL of PMAY-G and also uploaded the details on AwaasSoft.

2. In this connection, it is stated that in order to ensure a uniform criteria for identification of such households is followed all through out the country, the following procedure has been prescribed :-

- I. States / UT to ensure the following while identification of the eligible households under PMAY-G
 - a. The households should either be houseless or living in zero, one and two room house with kutchra wall and kutchra roof as per SECC data.
 - b. The identified households should not fulfil any one of the 13 exclusion parameters specified in SECC-2011 and mentioned in Annexure-I of the FFI.
 - c. The definition of kutchra roof would mean "Roof made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic / polythene, and hand made tiles) and kutchra wall would mean "Wall made of Grass/Thatch/Bamboo etc., plastic /

Page 1 of 3

polythene, mud / unburnt brick, wood and Stone not packed with mortar) as given in the SECC-2011 data for identification of the kutchha house.

- d. The identification of such households should be done by the Gram Sabha and the resolution of the Gram Sabha should clearly state that the households are identified after taking into account the above parameters. The Gram Sabha resolution should also mention the names of the head of the household to whom the house is to be allotted.
- e. The Claimant household could be a household whose name had appeared in the System generated list and was deleted by the Gram Sabha, or the household's name was not present in the system generated list. In both cases, adequate reasons for inclusion of the household needs to be recorded by the Gram Sabha.
- f. The list of households identified by Gram Sabha need to be submitted to the Competent Authority, notified by the State / UT Government for the purpose. The Competent Authority shall enquire into the list submitted by Gram Sabha and also applications received directly by such Authority and submit a report to the Appellate Authority, notified by respective State / UTs for the purpose.
- g. The Appellate Authority, based on the report of the Competent Authority, shall recommend the names of the left out beneficiaries who are found eligible for inclusion in the additional list.

II. A certificate detailing all the above process needs to be furnished by all the States / UTs that the identification of the beneficiaries has been done after following the above process.

III. Since capture of geo-tagged photograph of the house in which the beneficiary is currently residing, is mandatory under PMAY-G, the present dwelling/land of the households identified for inclusion in PWL also need to be geo-tagged. For this, a separate mobile application is being developed by the Ministry of Rural Development with the help of NIC. A separate module shall also be developed in Awaasoft to facilitate geo-tagging, uploading of Gram Sabha resolutions, etc. by States / UTs. The features of the mobile application and the module in AwaasSoft would be as follows :-

- a. The mobile application would have an incorporated feature wherein while capturing the photograph of the existing house would mandatorily ask to tick the pre-dominant material used for roof and wall. The option of the material will only be those identified as kutchha material as per SECC data.
- b. Further while capturing the geo-tagged photograph, the mobile application would have the feature to capture the 13 automatic exclusion parameters, 5

automatic inclusion / compulsory inclusion criteria and 5 deprivation parameters

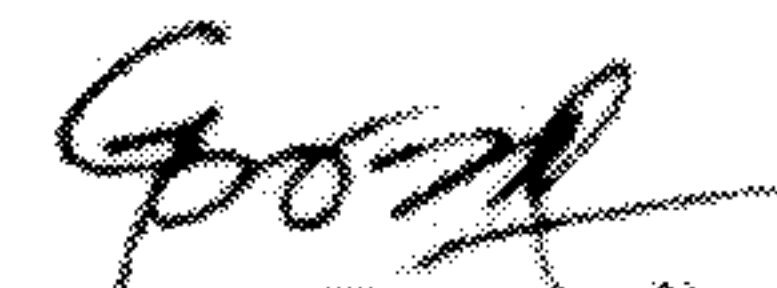
- c. A module which is being developed in AwaasSoft wherein the geo-tagged photographs captured using the mobile application are stored would have a provision of storing GP wise photographs.
- d. The AwaasSoft module would also have a provision for uploading of Gram Sabha Resolution indicating about identification of left out households after following due procedure and also having the list of heads of such households.

IV. Once all the above process is completed, Ministry of Rural Development would conduct electronic verification of the photographs of the houses uploaded viz., through space technology. Further, Ministry of Rural Development would undertake physical verification on sample basis of the houses uploaded on AwaasSoft. The physical verification involves the aspects whether the existing house is kutchha (both wall and roof are made of kutchha material specified in SECC), Gram Sabha resolution, report by the competent authority after due enquiry, applications submitted by individuals if any, recommendation of the appellate authority.

V. After all the above mentioned process have been completed, a decision would be taken about the number of households (over and above the SECC based list) that can be provided assistance under PMAY-G State/UT-wise. Thereafter approval of the Competent Authority for providing assistance to such households under PMAY-G would be sought.

3. In view of the above, it is requested that all the States / UTs may adopt the above prescribed procedure while identification of the beneficiaries who though eligible for assistance under PMAY-G as per the specified parameters have not been included in the Permanent Wait List. This exercise may be completed by 31st March, 2018.

Yours faithfully,



(Gaya Prasad)

Director (RH)

Tel: 011-23388431

Email:- gaya.prasad@nic.in

Copy to: NIC, MoRD for information and necessary action.

Page 3 of 3